



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 331] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 18, 2019/आश्विन 26, 1941
No. 331] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 18, 2019/ASVINA 26, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2019

(प्रकरण सं. ओ आई (सीवीडी)-05/2019)

विषय : इंडोनेशिया से स्टेनलैस स्टील के फ्लैट उत्पादों के आयातों से संबंधित सब्सिडीरोधी जांच की शुरूआत

फा.सं.6/16/2019-डीजीटीआर:—यतः इंडियन स्टेनलैस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन (आईएसएसडीए), जिंदल स्टेनलैस लिमिटेड (जेएसएल) और जिंदल स्टेनलैस (हिसार) तथा जिंदल स्टेनलैस स्टीलवे लिमिटेड (जेएसएसएल) (जिसे यहां आगे “याचिकाकर्ता” अथवा “घरेलू उद्योग” भी कहा गया है), ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें इंडोनेशिया (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) से स्टेनलैस स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पादों (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया है), के सब्सिडीकरण का आरोप लगाया गया है और संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने के लिए सब्सिडीरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया है।

क. सब्सिडीकरण का आरोप

- याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों/निर्यातकों को सार्वजनिक निकायों सहित संबद्ध देश की सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों द्वारा प्रदत्त कार्रवाई योग्य सब्सिडीयों से लाभ मिल रहा है। याचिकाकर्ताओं ने सार्वजनिक डोमेन में यथा उपलब्ध संगत कानूनों, नियमों और विनियमों और संगत सरकारी

एजेंसियों और लोक निकायों की अधिसूचनाओं और अन्य जाँचकर्ता प्राधिकारियों जिन्होंने ऐसी स्कीमों की विस्तृत जाँच की है और प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी कार्यक्रम की मौजूदगी निर्धारित की है, पर भरोसा किया है।

ख. परामर्श

3. एएससीएम के अनुच्छेद 13 के अनुसार नई दिल्ली में इंडोनेशिया की सरकार के प्रतिनिधियों के साथ जाँच पूर्व परामर्श किया गया था। संबद्ध देश की सरकार के प्रतिनिधियों की टिप्पणियों को रिकार्ड में लिया गया है।

ग. सब्सिडी कार्यक्रम

4. याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदत्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य से पता चलता है कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों और निर्यातकों को इंडोनेशिया की सरकार और /या अन्य सार्वजनिक निकायों द्वारा प्रदत्त नीचे यथा सूचीबद्ध अनेक सब्सिडी स्कीमों/कार्यक्रमों से लाभ मिला है।

पर्याप्त मूल्य से कम पर सुविधाओं और कच्ची सामग्री के रूप में अभिज्ञात स्कीमें

कार्यक्रम सं 1: विद्युत के लिए कोयले की कीमत की बेंचमार्किंग

कार्यक्रम सं 2: निर्यात के लिए न्यूनतम मूल्यवर्धन

कार्यक्रम सं 3: खनिज धातु और कोयले के लिए बेंचमार्क कीमत निर्धारण

कार्यक्रम सं 4: घरेलू बाजार दायित्व (डीएमओ) स्कीम

निर्यात वित्तपोषण और निर्यात ऋण के रूप में पहचान की गई योजनाएँ

कार्यक्रम संख्या 5: निर्यात ऋण बीमा/नुकसान से प्रतिपूर्ति

कार्यक्रम संख्या 6: निर्यात क्रेडिट गारंटी

कार्यक्रम संख्या 9: इंडोनेशिया एग्जिम से निर्यात वित्तपोषण

कर प्रोत्साहन और वैट छूट के रूप में अभिज्ञात योजनाएं

कार्यक्रम संख्या 7: आयकर में कटौती

कार्यक्रम संख्या 8: कर अवकाश

कार्यक्रम संख्या 10: आयात शुल्क से छूट

कार्यक्रम संख्या 11: आयात शुल्क वापसी

कार्यक्रम संख्या 13: शुद्ध कर योग्य आय में कमी

कार्यक्रम संख्या 14: नुकसान को आगे ले जाना

कार्यक्रम संख्या 15: आयात शुल्क आस्थगन

कार्यक्रम संख्या 16: उत्पादन उद्देश्य के लिए कच्चे माल और सहायक वस्तुओं पर शुल्क छूट

कार्यक्रम संख्या 17 आयातों पर आयकर से छूट

कार्यक्रम संख्या 18 एसईजेड में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए कटौती

कार्यक्रम संख्या 19 पायनियर उद्योग का दर्जा

कार्यक्रम संख्या 23 वैट की वापसी

वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान के रूप में अभिज्ञात योजनाएं

कार्यक्रम संख्या 21: भूमि कर में कटौती।

5. निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य सब्सिडी की जांच करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं, जिन्हें जांच की प्रक्रिया के दौरान संबद्ध वस्तु के उत्पादकों और निर्यातकों के लिए उपलब्ध और मौजूद पाया जाता है।

घ. क्षति और कारणात्मक संबंध का आरोप

6. आवेदक ने नियमों में अधीन यथा विहित घरेलू उद्योग को 'क्षति' से संबंधित विभिन्न मानदंडों के बारे में जानकारी दी है। आवेदक द्वारा प्रदत्त साक्ष्य से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि संबद्ध देशों से कथित सब्सिडीप्राप्त आयात के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
7. याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया है कि पीओआई में आयातों में वृद्धि, सकारात्मक कीमत कटौती, इंडोनेशिया में उत्पादकों की अतिरिक्त क्षमता और निर्यात उन्मुखीकरण, क्षमता वृद्धि, संबद्ध देश पर कुछ देशों द्वारा लागू व्यापार उपचार उपायों को ध्यान में रखते हुए आयात घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का खतरा उत्पन्न कर रहे हैं।

ड. जाँच की शुरुआत

8. प्राधिकारी पाते हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के उत्पादन या निर्यात पर प्रतिसंतुलन योग्य सब्सिडी की मौजूदगी का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है और इस तरह के सब्सिडीप्राप्त आयात घरेलू उद्योग को उसकी मात्रा और मूल्य प्रभाव के माध्यम से वास्तविक क्षति का कारण बन रहे हैं। इसके अलावा, घरेलू उद्योग द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि सब्सिडीप्राप्त आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का खतरा है।
9. उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए, प्राधिकारी संबंधित नियमावली के नियम 6 के अनुसार कथित सब्सिडी और घरेलू उद्योग को परिणामी वास्तविक क्षति और क्षति के खतरे की जांच की शुरुआत करते हैं, ताकि कथित सब्सिडी की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

च. घरेलू उद्योग

10. यह आवेदन भारतीय स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन (आईएसएसडीए), जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड (जेएसएल) और जिंदल स्टेनलेस (हिसार) लिमिटेड और जिंदल स्टेनलेस स्टीलवे लिमिटेड (जेएसएसएल) ने दायर किया है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार याचिकाकर्ता कंपनियों का कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है।
11. याचिकाकर्ता कंपनियों ने बताया है कि वे इंडोनेशिया के एक निर्यातक अर्थात् पीटी जिंदल स्टेनलेस इंडोनेशिया से संबंधित हैं। हालांकि याचिकाकर्ताओं ने यह प्रमाणित किया है कि कंपनी ने जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात नहीं किया है। इस प्रकार, यह याचिकाकर्ता कंपनियों की पात्रता को प्रभावित नहीं करता है।
12. अतः प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि याचिकाकर्ता कंपनियां नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

छ. विचाराधीन उत्पाद

13. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद 'स्टेनलैस स्टील के फ्लैट रोलड उत्पाद' हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:
- क. ब्लेड स्टील, या व्यावसायिक रूप से रेजर ब्लेड ग्रेड स्टील जिसे रेजर के उत्पादन में उपयोग किया जाता है।
- ख. मौद्रिक सिक्कों के उत्पादन में प्रयुक्त 73269099 के अंतर्गत आने वाला काइन ब्लैंक।
14. विचाराधीन उत्पाद का कई अलग-अलग रूपों में लेन-देन किया जा सकता है, जैसे कॉइल, शीट, प्लेट, सर्कल, स्ट्रिप्स या अन्यथा। उत्पाद के सभी रूप विचाराधीन उत्पाद के दायरे में हैं।
15. विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 72 में सीमाशुल्क उपशीर्ष सं 7219 और 7220 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। तथापि सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जाँच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

ज. पीसीएन

16. याचिकाकर्ताओं ने एक उत्पाद कोडिंग प्रणाली का प्रस्ताव किया है। याचिकाकर्ताओं ने ग्रेड, रूप, चौड़ाई, मोटाई और फिनिश को विभिन्न उत्पाद प्रकार (पीसीएन) माना है। हालाँकि, स्टेनलेस स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पादों के आयात के संबंध में 3 जुलाई 2019 को अधिसूचना 6/12/2019-डीजीटीआर द्वारा शुरू की गई एक समानांतर पाटनरोधी जांच में, प्राधिकारी ने कुछ कारकों अर्थात् उत्पाद का प्रकार, उत्पाद का ग्रेड, उत्पाद का रूप, उत्पाद की चौड़ाई, उत्पाद की मोटाई और फिनिश के आधार पर पीसीएन कार्यप्रणाली को अपनाने का निर्णय लिया था। वही पद्धति जो दिनांक 14/08/2019 की अधिसूचना संख्या 6/12/2019-डीजीटीआर द्वारा प्रकाशित की गई थी उसी पद्धति को वर्तमान जाँच में अपनाया जाना प्रस्तावित है।

झ. समान वस्तु

17. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु, संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु है। यह बताया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तु के बीच कोई खास अंतर नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि ये दोनों वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के "समान वस्तु" माना जा रहा है।

ब. शामिल देश

18. वर्तमान जाँच में शामिल देश इंडोनेशिया है।

ट. जांच अवधि

19. वर्तमान जाँच में जाँच की अवधि (पीओआई) अप्रैल 2018 – मार्च 2019 तक की है। तथापि क्षति जाँच अवधि में 2015–2016, 2016–2017, 2017–2018, और जाँच की अवधि शामिल होगी।

ठ. प्रक्रिया और सूचना प्रस्तुत करना

20. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों व प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से लिखा जा रहा है। वर्तमान जाँच में भाग लेने का इच्छुक कोई अन्य पक्षकार निम्नलिखित पते पर लिख सकता है :

निर्दिष्ट प्राधिकारी**व्यापार उपचार महानिदेशालय****वाणिज्य विभाग,****वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,****चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001**

21. संबंधित नियमावली के नियम 7(5) के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के औद्योगिकी उत्पादकों और प्रतिनिधि उपभोक्ता संगठनों को भी सविस्ती, क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में जाँच से संगत सूचना प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। कोई अन्य हितवद्ध पक्षकार भी जांच से संगत कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है।

ड. समय-सीमा

22. वर्तमान जाँच संबंधित कोई सूचना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। तथापि संबद्ध देश की सरकार, ज्ञात निर्यातक और

आयातक जिन्हें अलग से लिखा गया है, को उन्हें अलग से प्रेषित पत्र की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर सूचना प्रस्तुत करना अपेक्षित है। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

ढ. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

23. नियमावली के नियम 8 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों के लिए प्राधिकारी को प्रदत्त किसी गोपनीय सूचना का अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए।
24. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।
25. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।
26. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध/रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।
27. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
28. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ण. असहयोग

29. नियम 7(8) के अनुसार, यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

त. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

30. नियम 7(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 2019

Case No. OI (CVD)- 05 /2019

Subject: Initiation of Anti-Subsidy Investigation concerning imports of Flat Products of Stainless Steel from Indonesia.

F.No.6/16/2019-DGTR:—Whereas, Indian Stainless Steel Development Association (ISSDA), Jindal Stainless Limited (JSL) and Jindal Stainless (Hisar) Limited and Jindal Stainless Steelway Limited (JSSL) (hereinafter referred to as “petitioners” or “Domestic industry”) have filed an application on behalf of Domestic industry before the Designated Authority, in accordance with the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and determination of injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter referred to as the Rules), alleging subsidization of Flat Rolled Products of Stainless Steel (referred to as ‘subject goods’ or ‘product under consideration’) from Indonesia (hereinafter referred to as ‘subject country’) and requested for initiation of an anti-subsidy investigation for levy of countervailing duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

A. Allegation of Subsidization

2. The petitioners have alleged that the producers/exporters of the subject goods in the subject country have benefitted from the actionable subsidies provided at various levels by the Government of the subject country, including ‘Public bodies’. The petitioners have relied upon the relevant Laws, Rules and Regulations and other Notifications of the relevant Government Agencies and Public Bodies as available in the public domain and in the determination of other investigating Authorities who had conducted a comprehensive investigation of such schemes and concluded existence of countervailable subsidy programs.

B. Consultation

3. In terms of Article 13 of ASCM pre-initiation consultations were held with the representatives of the Government of Indonesia. The comments of representatives of the Government of the subject country have been taken on record.

C. Subsidy Programs

4. The prima facie evidence provided by the petitioners show that the producers and exporters of the subject goods in the subject country have benefitted from a number of subsidy schemes/programs, granted by the Government of Indonesia and/or their respective public bodies as listed below:

Schemes identified as utilities and raw material at less than adequate remuneration

Program No 1	Benchmarking Coal Price for Electricity
Program No 2	Minimum value addition for export
Program No 3	Benchmark pricing for Minerals, Metals and Coal
Program No 4	Domestic Market Obligation (DMO) Scheme

Schemes Identified as Export Financing and Export Credit

Program No 5	Export Credit Insurance/reimbursement from losses
Program No 6	Export Credit Guarantees
Program No 9	Export Financing from Indonesia EXIM

Schemes Identified as Tax Incentives and VAT Exemption

Program No 7	Reduction of Income tax
Program No 8	Tax Holiday

Program No 10	Exemption on Import Duty
Program No 11	Import Duty Drawback
Program No 13	Reduction of Net Taxable Income
Program No 14	Carry Forward of Losses
Program No 15	Postpone on Import Duty
Program No 16	Exemption of Duty on Raw Material and Supporting Goods for Production Purpose
Program No 17	Exemption from Income Tax on Imports
Program No 18	Reduction for Investors investing in SEZ
Program No 19	Pioneer Industry Status
Program No 23	Refund of VAT

Schemes Identified as Provision for Goods & Services

Program No 21	Deduction in Land Tax
---------------	-----------------------

5. The Designated Authority reserves the right to investigate other subsidies, which may be found to exist and availed by the producers and exporters of the subject goods, during the course of the investigation.

D. Allegation of Injury and Causal Link

6. The petitioners have furnished information on various parameters relating to 'injury' to the domestic industry as prescribed under the Rules. The evidence provided by the petitioner's prima facie shows material injury to the domestic industry has been caused by the alleged subsidized imports from the subject country.
7. The petitioners have also claimed that imports are causing threat of material injury, considering substantial increase in imports in the POI, positive price undercutting, surplus capacities, capacity addition and high export orientation of producers in Indonesia and trade remedial measure imposed by various countries on the subject goods.

E. Initiation of the Investigation

8. The Authority finds that there is prima facie evidence of existence of countervailable subsidies on production and export of the subject goods in the subject country and such subsidized imports are causing material injury to the domestic industry through their volume and price effects. Further, the threat of material injury to the domestic industry on account of subsidized imports has also been alleged by the domestic industry.
9. In view of the above position, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged subsidization and consequent material injury and threat of injury to the domestic industry in terms of Rule 6 of the Rules supra, to determine the existence, degree and effect of alleged subsidization and to recommend the amount of countervailing duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

F. Domestic Industry

10. The application has been filed Indian Stainless Steel Development Association (ISSDA), Jindal Stainless Limited (JSL) and Jindal Stainless (Hisar) Limited and Jindal Stainless Steelway Limited (JSSL) as per the evidence available on record, production of the petitioner companies accounts for a major proportion of the total domestic production.
11. The petitioner companies have stated that they are related to an exporter in Indonesia namely PT Jindal Stainless Indonesia. However, the petitioners have certified that the company has not exported the subject goods to India during the period of Investigation. Thus, it does not affect the eligibility of the petitioner companies.
12. The Authority, therefore, determines that the petitioner companies constitute the domestic industry within the meaning of Rules 2(b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rules 6(3) of the Rules supra.

G. Product under consideration

13. The product under consideration in the present investigation is "Flat Rolled Products of Stainless Steel, excluding the following
 - a. Blade Steel, or commercially known as razor blade grade steel used in the production of razor

b. Coin Blank falling under 73269099 used in the production of monetary coins.

14. Product under consideration can be transacted in a number of different forms, such as coils, sheets, plates, circles, strips or otherwise. All forms of the product are within the scope of the product under consideration.
15. The product under consideration falls under customs sub-heading nos. 7219 and 7220 of Chapter 72 of the Customs Tariff Act, 1975. The classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigations.

H. PCN

16. Petitioners have proposed a Product Coding system. Petitioners have considered grades, forms, width, thickness and finish as different product type (PCN). However, in a parallel anti-dumping investigation concerning imports of Flat Rolled Products of Stainless Steel initiated vide Notification 6/12/2019-DGTR dated 03.07.2019, the Authority had decided to adopt the PCN Methodology based on certain factors viz. product type, grade of the product, form of the product, width of the product, thickness and finish of the product. The same methodology as published vide notification 6/12/2019-DGTR dated 14/08/2019 is proposed to be adopted in this investigation.

I. Like Article

17. The petitioners have claimed that the goods produced by the domestic industry are like article to the subject goods originating in or exported from the subject country. It has been stated that there is no significant difference in the subject goods produced by the petitioners and those exported from subject country. The petitioners claim that the two are technically and commercially substitutable. For the purpose of present investigation, the subject goods produced by the domestic industry are being treated as 'like articles' to the subject goods imported from the subject country.

J. Country Involved

18. The country involved in the present investigation is Indonesia.

K. Period of Investigation

19. The period of investigation (POI) in the present investigation is April 2018- March 2019. The injury investigation period will, however, cover the periods 2015-16, 2016-17, 2017-18 and the period of investigation.

L. Procedure & Submission of information

20. The exporters in the subject country, importers and users in India known to be concerned with the product and the domestic industry are being informed separately to enable them to provide all information relevant in the form and manner prescribed. Any other party interested to participate in the present investigation may also write to:

The Designated Authority

**Directorate General of Trade Remedies Department of
Commerce**

Ministry of Commerce & Industry

4th Floor, Jeevan Tara Building,

5 Parliament Street, New Delhi-110001

21. As per Rule 7(5) of the Rules supra, the Designated Authority is also providing opportunity to the industrial users of the product under investigation, and to represent consumer organizations who can furnish information which is relevant to the investigation regarding subsidy, injury and causal link. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time limits set out below.

M. Time limit

22. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than 40 (forty) days from the date of publication of this notification. The Government of the subject country, known exporters and importers, who are being addressed separately, are however required to submit the information within 40 (forty) days from the date of the letter addressed to them separately. If no information is received within the prescribed time limit or the submitted information is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

N. Submission of Information on Non-Confidential basis

23. In terms of Rule 8 of the Rules, the interested parties are required to submit a non-confidential version of any confidential information provided to the Authority. In case confidentiality is claimed on any part of the

questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

24. Information supplied without any mark as "Confidential" shall be treated as non- confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies each of the confidential version and the non-confidential version must be submitted.
25. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.
26. The non- confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked / summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary; a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
27. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
28. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such confidential information.

O. Non cooperation

29. In terms of Rule 7(8), in case where an interested party refuses access to or does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

P. Inspection of Public File

30. In terms of Rule 7(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority